उत्तर उजाला

गुरुवार 14 मार्च, 2019

जैसे सूर्य सबको एक-सा प्रकाश देता है। बरसात सब के लिए बरसती है। उसी तरह विद्यावृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिए। - महात्मा गांधी

औद्योगिक विकास दर

देश की औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर जनवरी महीने में धीमी पड़ कर 1.7 प्रतिशत रह गई। विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से पूंजीगत सामान और उपभोक्ता सामान क्षेत्र के सुस्त प्रदर्शन की वजह से आईआईपी की वृद्धि दर कम हुई है। दूध, खाद्य पदार्थों की कीमतें अधिक होने की वजह से फरवरी में खुदरा महंगाई दर 2.57 फीसदी पर रही। यह चार महीने का उच्च स्तर है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बीएसई सेंसेक्स 48 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछली सरकार के दूसरे कार्यकाल (2009-14) में यह 180 प्रतिशत और पहले कार्यकाल (2009-14) में 78 प्रतिशत बढ़ा था। बड़ी बात यह है कि यूपीए 2 के शासन में सेंसेक्स में बढ़ोतरी के आंकड़े का बड़ा हिस्सा 13 सितंबर, 2013 से 2014 में कार्यकाल की समाप्ति के बीच बाद प्राप्त हुआ। नौ महीने के इस दौर में सेंसेक्स 25 प्रतिशत मजबूत हुआ था जबकि 2004 में मनमोहन सरकार के शपथ ग्रहण के शुरुआती 51 महीने (सवा चार वर्ष) में सेंसेक्स 42 प्रतिशत चढ़ा था। अर्थव्यवस्था का विकास न होने से बेरोजगारी की समस्या बेतहाशा बढ़ गई है। डिग्रीधारी युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आर्थिक वृद्धि सीधे-सीधे देश के मिजाज से जुड़ी है और नकारात्मक व डर के माहौल में इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। औद्योगिक विकास की घटती दर का अनुमान यहां के युवाओं की कौशलता पर भी निर्भर है। दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम की प्रमुख गिन्नी रोमेटी ने कहा है कि भारतीयों के पास जरूरी कौशल का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ नये जमाने के रोजगार अधिक मात्रा में सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सभी को डिग्री से इतर शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। कुल 180 अरब डॉलर के घरेलू सॉफ्टवेयर उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आईबीएम की चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोमेटी ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है और केवल भारत तक सीमित नहीं है। असल में डिग्री के मुकाबले कौशल ज्यादा जरूरी है। आज इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लाखों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्हें अगर शुरुआती स्तर पर नौकरी मिलती भी है तो अनुभव रखने वाले अर्द्ध कुशल कामगारों से बहुत कम मेहनताना मिलता है। लाखों इंजीनियरों तथा बिजनेस स्कूल से डिग्री लेने वाले युवाओं में करीब तीन चौथाई रोजगार के काबिल नहीं हैं। यह देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ दाखिला प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। निजी आर्थिक शोध संस्थान सीएमआईई के आंकड़े में कहा गया है कि फरवरी की स्थिति के अनुसार 3.12 करोड़ युवा पूरी सक्रियता के साथ रोजगार तलाश रहे हैं। कुल 1.35 करोड़ की आबादी में 60 प्रतिशत से अधिक 35 साल से कम के हैं। धारणा के विपरीत पर्याप्त मात्रा में रोजगार हैं और उतनी ही संख्या में युवा नौकरी खोज रहे हैं लेकिन कौशल की कमी रोड़ा है और यह एक वास्तविक समस्या है। पिछले वर्षों में चालू की गई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे नारों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ा।

महिलाओं के लिए अच्छी पहल

लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। नामांकन की तिथि निकट देख प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़े नेताओं की बैठकें हो रही हैं। यूं तो हर राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी की बात करते हैं। मगर, उन्हें लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने में परहेज करते हैं। चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में हैं। ऐसे में टिकट देने में महिलाओं की अनदेखी की जाती है। लेकिन, तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 41 फीसदी महिलाओं को टिकट देकर अन्य राजनीतिक दलों को आईना दिखाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य में लोकसभा की सभी 42 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्य की 42 सीटों में से 17 सीटों पर महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। जबकि, 2014 में इस पार्टी की 35 फीसदी सांसद महिलाएं थी। तृणमूल कांग्रेस ने जिन महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, उनमें काकोली घोष दस्तीदार, महुआ मोइत्रा और फिल्म स्टार मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां हैं। सूची में पूर्व रेल मंत्री दिवंगत एबीए गनी खान चौधरी की भतीजी मौसम नूर भी शामिल हैं। नूर हाल ही में कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं। हालांकि, सूची में टीएमसी के कई प्रमुख चेहरों मसलन अखिल भारतीय महासचिव सुब्रता बख्शी, हार्वर्ड प्रोफेसर सुगाता बोस, अल्पसंख्यक चेहरों में प्रमुख इदरीस अली, अभिनेत्री संध्या रॉय और उमा सोरेन को टिकट नहीं दिया गया है। इन सभी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) 33 फीसदी सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारेगा। इस घोषणा का मतलब यह है कि बीजद राज्य में लोकसभा की 21 सीटों में से कम से कम सात सीटों पर महिलाओं को टिकट देगा। इस समय उड़ीसा से लोकसभा में तीन महिला सांसद हैं। हालांकि, नवीन पटनायक ने विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा में इस समय 12 महिला विधायक हैं। एक सम्मेलन में नवीन पटनायक ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम देश में महिला सशक्तिकरण की अगुवाई करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को उन्नत देश बनना है तो महिला सशक्तिकरण ही इसका एकमात्र रास्ता है। बहरहाल, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल की पहल का स्वागत किया जाना चाहिये। साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि अन्य राजनीतिक दल भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।

सादगी के तर्क

प्रेरक प्रसंग

एक बार लाल बहादुर शास्त्री एक अधिवेशन में सम्मिलित होने भुवनेश्वर गए। अधिवेशन में जाने से पहले वे स्नान करने लगे। इसी बीच दयाल महोदय उनके सूटकेस से उनका खादी का कुर्ता निकालने लगे ताकि अधिक समय व्यर्थ न हो। उन्होंने एक कुर्ता निकाला। उन्होंने देखा कि कुर्ता फटा हुआ था। उन्होंने वह कुर्ता वापस सूटकेस में रख दिया और उसमें से दूसरा कुर्ता निकाला। ये देखकर वह चकित रह गए कि वह कुर्ता पहले वाले कुर्ते से भी अधिक फटा हुआ था। उन्होंने शास्त्री जी के सारे कुर्ते देखे। तकरीबन सारे कुर्ते फटे हुए थे। दयाल जी परेशान हो गए कि अब शास्त्री जी क्या पहन कर अधिवेशन में जायेंगे। जब शास्त्री जी स्नान कर बाहर आये तो दयाल जी ने उन्हें बताया कि सारे कुर्ते फटे हुए हैं। शास्त्री जी ने उन्हें समझाया कि अभी सर्दी का मौसम है। फटे कुर्ते कोट के नीचे पहने जा सकते हैं।

विरोधाभासों से बोझिल महागठबंधन

✍ सीमा पासी

यही कारण है कि विपक्ष के लिये केवल एक मुद्दा ही बचा है और वो है मोदी हटाओ। जहाँ तक राजनीतिक संभावनाओं की बात की जाए तो यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो मोदी को हटाना उसके लिये मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। अभी यूपी को छोड़कर कहीं भी गठबन्धन की तस्वीर साफ नहीं हुई है, इसलिये अभी यह कहना मुश्किल है कि विपक्ष अपने इरादों में सफल हो सकता है या नहीं लेकिन अभी से यह हालात बनते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष अपने विरोधाभासों के बोझ से दबकर अपना भविष्य दांव पर लगाने जा रहा है।

विपक्ष के लिये 2019 का लोकसभा चुनाव करो या मरो की तरह बन चुका है और यही कारण है कि विपक्ष के लिये केवल एक मुद्दा ही बचा है और वो है मोदी हटाओ। जहां तक राजनीतिक संभावनाओं की बात की जाए तो यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो मोदी को हटाना उसके लिये मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। अभी यूपी को छोड़कर कहीं भी गठबन्धन की तस्वीर साफ नहीं हुई है, इसलिये अभी यह कहना मुश्किल है कि विपक्ष अपने इरादों में सफल हो सकता है या नहीं लेकिन अभी से यह हालात बनते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष अपने विरोधाभासों के बोझ से दबकर अपना भविष्य दांव पर लगाने जा रहा है। मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिये विपक्ष ने बहुदलीय व्यवस्था वाले देश में विचारधारा की जगह अपने-अपने स्वार्थों को ही महत्त्व दिया है। मोदी का विरोध मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हो गया है। यहां तक कि भाजपा विरोध भी भुला दिया गया है। इस अन्धे विरोध ने भाजपा के कुछ नेताओं के लिये भी संभावनाओं के द्वार खोल दिये हैं क्योंकि भाजपा की 150 से 200 के बीच सीटें आने पर विपक्ष के कई दल मोदी के अलावा किसी अन्य भाजपा नेता के नेतृत्व की छतरी के नीचे आने में गुरेज नहीं करेंगे। वैसे भी मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वे एक ऐसी लंगड़ी सरकार का नेतृत्व करने की कोशिश भी करें। किसी अन्य भाजपा नेता के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार बनने की संभावनाएं इसलिये भी ज्यादा हैं क्योंकि भाजपा को छोड़कर किसी अन्य दल के नेतृत्व में बनी सरकार ज्यादा देर तक टिक नहीं पायेगी। अभी तक शान्त दिख रहे दल इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ममता, मायावती और राहुल अपनी ढपली बजाते रहें लेकिन अभी उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। ममता को उनके ही राज्य में भाजपा ने बुरी तरह से घेर लिया है और वे अपने ही राज्य में नुकसान उठाने जा रही हैं। 38 सीटों पर लड़ने वाली मायावती के सहयोगी अखिलेश चुनाव परिणामों के बाद कभी भी पलटी मार सकते हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व विपक्षी नेता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वैसे भी विरोधाभासों से भरे गठबन्धन का नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में कहीं से भी नजर नहीं आती है। वैसे कांग्रेस का विरोध केवल मोदी तक सीमित नहीं है बल्कि उसका भाजपा विरोध मोदी विरोध से किसी प्रकार भी कम नहीं है इसलिये इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिये किसी को भी समर्थन दे सकती है। संघ का विचार समूह राजनीतिक हलचलों पर गहरी नजर रखता है और भाजपा उसी से निर्देशित होती है। यदि मोदी के नेतृत्व में भाजपा 200 से 250 सीटें नहीं हासिल कर सकी तो हो सकता है कि संघ भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिये मजबूर कर दे क्योंकि संघ जानता है कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक विरोधाभासों के बोझ तले इतने दबे हुए हैं कि वो सरकार बना भी लें तो ज्यादा दिन तक सरकार चला नहीं पायेंगे और दूसरी बात यह है कि ऐसी सरकार कम चले या ज्यादा, भाजपा का फायदा ही होगा। मोदी सरकार के पांच साल के शासन ने ऐसी लकीर खींच दी है जिसको पार करना किसी भी गठबन्धन सरकार के लिये संभव नहीं है और दूसरी तरफ वर्तमान में जनता की उम्मीदों को पूरा करना किसी भी सरकार के लिये अब संभव नहीं रह गया है। अब विरोधाभासों की बात करें तो मायावती और अखिलेश के बीच भी विरोधाभास कम नहीं हैं। मायावती जिस घोटाले में फंसी हुई हैं उसमें कार्यवाही की शुरूआत अखिलेश सरकार के समय ही हुई थी और मायावती के खिलाफ ज्यादातर मामले समाजवादी पार्टी द्वारा ही दर्ज किये गये हैं। यही हाल अखिलेश यादव का है। उनके खिलाफ भी मामले बसपा द्वारा ही दर्ज कराये गये थे। आज बेशक दोनों नेता अपने आपको फंसा पाकर भाजपा को कोस रहे हैं लेकिन दोनों ही जानते हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को फंसाया है लेकिन एक सच यह भी है कि उन्होंने गलत नहीं फंसाया है, इसलिये देर सवेर उन पर लगे आरोप सच साबित हो जाने वाले हैं। एक विरोधाभास यह भी है कि 2017 से पहले दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और आज उनके नेता आपस में मिल गये हैं तो क्या जरूरी है कि वो भी आपस में मिल जाएंगे। कांग्रेस की बात की जाएं तो यूपी में उसे सपा-बसपा ने अपने गठबन्धन से बाहर रखा है इसलिये चुनाव प्रचार में इनमें भी आरोप-प्रत्यारोप की दौर चलने वाला है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि विपक्ष के ज्यादातर दल कांग्रेस विरोध में ही पैदा हुए हैं और उनके कार्यकर्ताओं के मन में गहरा कांग्रेस विरोध जड़े जमाये हुए है। बेशक नेता अपने-अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो लेकिन कार्यकर्ता इतनी आसानी से जुड़ने वाले नहीं हैं। एक बड़ा विरोधाभास यह भी है कि कांग्रेस के समर्थन से बनने वाली पिछली सरकारों को कांग्रेस ने बीच रास्ते खुद ही लंगड़ी मारकर गिराया है और ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से बदला लेने का विचार विपक्षी दलों को क्यों नहीं आयेगा। यह सच तो आपके सामने ही है कि जब से कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकार बनाई है, तभी से विपक्षी दलों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है क्योंकि जहां वे भाजपा को कमजोर देखना चाहते हैं, वही वो कांग्रेस को भी मजबूत होता नहीं देख सकते। कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व भले ही बंगाल में ममता के साथ दिखाई दे लेकिन स्थानीय इकाई भाजपा से ज्यादा ममता के खिलाफ है। दिल्ली में भी स्थानीय कांग्रेसी नेता केजरीवाल के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोक रही है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ कोई चलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने की रणनीति में कामयाब नहीं हो पाई थी। क्या यह सच आपको नहीं पता है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों में केवल नेतृत्व को लेकर ही मतभेद नहीं बल्कि विचारधारा में भी कहीं कोई मेल नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दलों की केवल एक विचारधारा आपस में मिलती है और वो है किसी भी तरीके से मोदी को हटाना। अब सवाल उठता है कि यदि ये लोग सचमुच में मोदी को हटाने में कामयाब हो गये तो उसके बाद कौन सी विचारधारा इन्हें एक रख सकेगी। तीन राज्यों की जीत के बाद कांग्रेस बदली-बदली नजर आ रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिये उन्हें केवल भाजपा विरोध तक सीमित रखना संभव नहीं है। यदि विपक्ष की सरकार बनती है तो कांग्रेसी कभी नहीं चाहेंगे कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो दूसरी तरफ विपक्षी राहुल या प्रियंका के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी को हटाना इतना आसान नहीं है जितना विपक्षी दल सोच रहे हैं। समस्या मोदी को हराना नहीं है बल्कि मोदी की जगह लेना समस्या है। यही कारण है कि जब भी नेतृत्व की बात आती है तो विपक्षी दलों का यही जवाब होता है कि हमारे पास बहुत नेता हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और चुनावों के बाद इस पर फैसला हो जायेगा। वास्तव में अगर अभी यह फैसला किया गया तो विपक्षी दलों की एकता की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए विपक्षी दलों के पास केवल एक मुद्दा है और वो मोदी को हटाना है लेकिन मोदी का विकल्प क्या होगा, इस पर बात करने की हिम्मत किसी भी दल के पास नहीं है। वास्तव में आज भाजपा ऐसी जगह आकर खड़ी हो गई है जहां उसकी जीत तो जीत होगी ही लेकिन हार भी जीत से कम नहीं होगी। भाजपा की तैयारियां भी कुछ ऐसी हैं कि यदि हम सरकार न भी बना पाये तो दूसरे को सरकार चलाने नहीं देंगे। इस बात का सबूत है इस बार का बजट जो चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिये जितने धन की जरूरत होगी उसे जुटाने में ही सारी मेहनत चली जाएंगी। यदि भाजपा की सरकार आती है तो वो नई योजनाओं को लाने की जगह इन्हें ही पूरा करने की कोशिश करेगी और यदि विपक्ष की सरकार आती है तो वो अपने वादे पूरे नहीं पाएगी। कुछ नया करना विपक्ष के लिये बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिये कर्जमाफी और यूनिवर्सल बैसिक इन्कम जैसी योजनाएं पूरा करना लगभग असंभव हो जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाजपा न केवल जीत के लिये तैयारी कर रही है बल्कि उसने अपनी हार की भी तैयारी कर ली है। भाजपा ने ऐसी लाइन खींच दी है जिसे पार करना न केवल विरोधाभासों के बोझ से दबी मजबूर सरकार के लिये बल्कि किसी मजबूत सरकार के लिये भी मुश्किल होगा।

आम चुनाव को नया सूरज बनाना होगा

✍ ललित गर्ग

इन चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होते ही सभी राजनैतिक दलों ने इसमें विजय प्राप्त करने के लिए अपनी कमर कसने की शुरुआत भी कर दी है परन्तु इन चुनावों को लेकर एक बड़ा प्रश्न है कि भारत को निर्मित करने का संकल्प एवं तैयारी किस दल ने दृढ़ता से प्रदर्शित नहीं की है। देखने में आ रहा है कि एक बार फिर राष्ट्रहित के मसलों से अधिक महत्व संकीर्ण स्वार्थ को दे दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

निर्वाचन आयोग की ओर से वर्ष 2019 के आम चुनाव की तिथियां तय कर देने के साथ ही चुनाव की सरगर्मियां उग्र हो गयी है, समूचा देश लोकतंत्र का उत्सव मनाने की दिशा में अग्रसर हो गया है। इन चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होते ही सभी राजनैतिक दलों ने इसमें विजय प्राप्त करने के लिए अपनी कमर कसने की शुरूआत भी कर दी है परन्तु इन चुनावों को लेकर एक बड़ा प्रश्न है कि भारत को निर्मित करने का संकल्प एवं तैयारी किस दल ने दृढ़ता से प्रदर्शित नहीं की है। देखने में आ रहा है कि एक बार फिर राष्ट्रहित के मसलों से अधिक महत्व संकीर्ण स्वार्थ को दे दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर राजनीतिक दल येन-केन-प्रकोरण सत्ता पाना चाहता है। चूंकि आम चुनाव देश के भविष्य के साथ राजनीति की भी दशा-दिशा तय करते हैं इसलिए आम मतदाता का इस भाव से जागरूक होना जरूरी है कि वह वोट के जरिये राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर होने के साथ-साथ राजनीतिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने कर दिशा में सार्थक पहल करें।

चुनाव लोकतंत्र का कुंभ हैए इसलिये चुनाव आयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वह ही केवल मतदाताओं को अपने हक का बिना किसी भय या लालच के मत देने का वातावरण बना सकता है परन्तु राजनैतिक दल इस वातावरण में अपने स्वार्थ का जहर इस तरह घोल देते हैं कि मतदाता उसके प्रभाव में आकर राष्ट्रीय समस्याओं से निगाह हटा लेते हैं किन्तु दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि ये मतदाता ही हर चुनाव में भूले-भटके राजनीतिज्ञों को सही राह दिखाते रहे हैं। इसलिये मतदाता की जिम्मेदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैए उसे जागरूक होना होगा, अपना मतदान सोच-समझ से विवेकपूर्ण ढंग से करना होगा। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह चुनावी अवसरों पर समाज में जाति या धर्म के नाम पर नफरत और घृणा फैलाने के प्रयास राजनीतिज्ञों द्वारा किये जाते रहे हैं उन पर भी इस बार चुनाव आयोग ने कड़ी निगाह रखने की घोषणा की है। यह निगाह ऐसी नजर बननी चाहिए जिससे सत्ता या विपक्ष का कोई भी नेता अपने दल की विचारधारा से न भटक सके। आम चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद एवं जम्मू-कश्मीर है। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अटूट अंग होने की एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि यहां के लोगों को भी अपनी मनपसन्द की राज्य सरकार को पाने का हक हमारे संवैधानिक छाते के नीचे उसी प्रकार दिया गया है जिस प्रकार भारत के किसी अन्य राज्य को। यहां राजनैतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ही हम पाकिस्तान समर्थकों की कमर तोड़ सकते हैं और ऐसे तत्वों को आम कश्मीरियों की निगाह में उनका दुश्मन साबित कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य में आयोग लोकसभा चुनाव तो करा रहा है मगर भंग विधानसभा के चुनाव कराने से उसने सुरक्षा का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिये हैं। जिस राज्य में लोकसभा चुनाव चालू परिस्थितियों में हो सकते हैं तो उनमें विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते, यह एक बड़ा प्रश्न है। भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा है कश्मीर। नाक है। कितनी कीमत चुका दी। चुका रहे हैं। वहां राजनीतिज्ञों की मांग है- स्वायत्तता। जनता ही मांग है- शांति। दोनों को इन्तजार है वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करना। कश्मीर घाटी दोषी और निर्दोषी लोगों के खून की हल्दीघाटी बनी हुई है। वहाँ लोगों को बन्दूक से सन्दूक तक लाना बेशक कठिन और पेचीदा काम है लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय एकता और निर्माण संबंधी कौन-सा कार्य पेचीदा और कठिन नहीं हैघ् यह चुनाव केवल दलों के भाग्य का ही निर्णय नहीं करेगाए बल्कि उद्योग, व्यापार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रक्षा आदि राष्ट्रीय नीतियों तथा राष्ट्र की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक हुआ है, वहां राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैंए उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा देश की एक अरब तीस करोड़ जनता को एक उन्नत एवं प्रगतिशील राष्ट्र को निर्मित करने की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगाए यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग की प्रभावी भूमिका प्रशंसनीय है। चुनावी आचार संहिता में प्रतिदिन कोई न कोई आदेश-निर्देश जोड़कर प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता-रेखा के भीतर लाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावों का नतीजा अभी लोगों के दिमागों में है। मतपेटियां क्या राज खोलेंगी, यह समय के गर्भ में है। पर एक संदेश इस चुनाव से मिलेगा कि अधिकार प्राप्त एक ही व्यक्ति अगर ठान ले तो अनुशासनहीनता की नकेल डाली जा सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया न केवल यथासंभव छोटी होनी चाहिए, बल्कि वह राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के छल-कपट से मुक्त भी होनी चाहिए। यह सही है कि पहले की तुलना में आज की चुनाव प्रक्रिया कहीं अधिक साफ-सुथरी और भरोसेमंद है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वह बेहद खर्चीली होने के साथ ही धनबल से भी दुष्प्रभावित होने लगी है। विडंबना यह है कि चुनाव लड़ने वाले इस आशय का शपथपत्र देकर छुट्टी पा लेते हैं कि उन्होंने तय सीमा के अंदर ही धन खर्च किया। यह विडंबना तब है जब हर राजनीतिक दल और खुद निर्वाचन आयोग भी इससे अवगत है कि आज चुनावों में किस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब तो हालत है कि पैसे बांटकर चुनाव जीत लेने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। समस्या यह है कि जहां जागरूक जनता चुनावी खामियों को दूर करने की जरूरत महसूस करती है वहीं राजनीतिक दल ऐसी किसी जरूरत पर ध्यान ही नहीं देते। चुनी हुई सरकारों को इस दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। आम चुनाव को भले ही लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा दी जाती होए लेकिन सच यह है कि इस उत्सव में राजनीतिक शत्रुता, राजनीतिक विसंगतियां एवं बेबुनियाद मुद्दे अपने चरम तक पहुंचता दिखता है। कई बार परस्पर विरोधी राजनीतिक दल-एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। वे न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन-अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए झूठ और कपट का सहारा भी लेते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव के मौके पर राजनीतिक विमर्श रसातल में चला जाए। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों से यह उम्मीद कम ही है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। अपने देश में यह एक बीमारी सी है कि बाकी समय तो हम सब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को कोसते हैं, लेकिन वोट देते समय जाति-मजहब को ही महत्व दे देते हैं। जात-पांत के आधार पर राजनीति इसीलिए होती है, क्योंकि एक तबका इसी आधार पर वोट देता है। सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार दल-टूटन व गठबंधन हो रहा है या हुआ है, इससे सबके मन में अकल्पनीय सम्भावनाओं की सिहरन उठती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र में टकराव होता है। विचार फर्क भी होता है। मन-मुटाव भी होता है पर मर्यादापूर्वक। अब इस आधार को ताक पर रख दिया गया है। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं होते। अवसरवादिता दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। यह भी बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। इन चुनावों को लेकर अब तक जो सुना गया उनके भावों को शब्द दें तो जन-संदेश यह होगा, स्थिरता किसके लिए, नेताओं के लिए या नीतियों के लिए। परिवर्तन की बात सब करते हैं। परिवर्तन की बातें भी बहुत हुईं, पर मुद्दों में परिवर्तन नहीं। आज वीआईपी और वीसीपी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। भारत में गॉड और गॉडमैन ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। लगता है किसी भगवान को इस स्थिति से बचाने के लिए आना होगा। प्रत्याशी अपनी टिकटों की कीमत जानते हैं, मूल्य नहीं। अपने गर्व को महत्व देते हैं, शहीदों के गौरव को नहीं। लोकतंत्र में भय कानून का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनैतिक दलों ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल सही रूप में नहीं निभा रहा है। सारे ही दल एक जैसे हैं। यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कान लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। जनता इन चुनावों और चुनावबाजों के चुनावी कर्मकाण्डों से हटकर एक मजबूत विकल्प तैयार करे। जनता को लोकतंत्र का असली अर्थ समझाए। जानकारी का अभाव मिटे। लोकतंत्र के सूरज को घोटालों, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थों के बादलों ने घेर रखा है। हमें किरण-किरण जोड़कर नया सूरज बनाना होगा। लोकशाही को जीवन्त करने के लिए हमें संघर्ष की फिर नई शुरूआत करनी पड़ेगी, वरना हर पाँच साल में मतपत्र पर ठप्पा लगाने का यह बासी हो चुका विकल्प हमें यूँ ही छलता रहेगा।

दृष्टिकोण

पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्ती जरूरी

पाकिस्तान आंतकवाद की शरण स्थली है, ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान असली चेहरा सामने आ गया है। इस हमले के बाद भारत की ओर से की गयी एयर स्ट्राइक ने आतंकवादियों और उनके आकाओं का मनोबल तोड़ने का काम किया है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर कई तरीके से दबाव डालने और सख्ती बरतने के संकेत दिये हैं। कुल मिलाकर पुलवामा आतंकी हमले के बाद विश्व बिरादरी में पाकिस्तान अलग-थलग हो गया है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने में भारत की कूटनीति का बड़ा हाथ है। लेकिन देश में ही चंद लोग ऐसे हैं जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं तो वहीं सेना की कार्यवाही पर सवाल और उंगुली उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आज जो व्यवहार व सख्ती भारत आज कर रहा है वो काफी पहले की जानी चाहिए थी। जानकार भी यही मानते हैं कि भारत को पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया कायम रखना चाहिए। जब भी हम आतंकवाद का नाम लेते हैं, तो कहीं न कहीं हम सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा दीमक है, जो दिन-प्रतिदिन हमारे देश को खोखला कर रहा है। इसकी मुख्य वजह रहा है पाकिस्तान, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शत-शत नमन उन वीर जवानों को जिन्होंने शहीद होकर देश का कर्ज अदा किया है। आज वीर जवान सरहद पर हैं, तभी हम अपने परिवार के साथ सही सलामत हैं। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को पूरा देश शत-शत नमन करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष-विपक्ष को आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भरसक यत्न करना होगा और केंद्र सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना होगा। यदि अब आतंकवाद को जवाब नहीं दिया, तो हिंदोस्तान में आतंकवाद की जड़ें और गहरी हो जाएंगी, जिन्हें उखाड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। वास्तव में जो लोग ये समझ बैठे थे कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा की गई शांति की पेशकश और कई बड़े देशों द्वारा दिये गए मध्यस्थता प्रस्ताव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मौजूदा तनाव की इतिश्री हो जाएगी, उनकी गलतफहमी गत दिवस दूर हो गई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायु सेनाध्यक्ष बीएस धनोआ ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का जो कदम उठाया गया है वह पीछे नहीं हटेगा। श्री मोदी ने तो साफ-साफ कह दिया कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारेंगे। एयर स्ट्राइक को भले ही इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा हो लेकिन देशहित के लिहाज से देखने पर ये लगेगा कि आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान शुरू किया गया है उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना यदि बीच में रोक दिया गया तो ये दोहरा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। पुलवामा हमले के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो सहानुभूति और समर्थन मिला वह अभूतपूर्व कहा जा सकता है। पहली बार पाकिस्तान को विश्व की लगभग सभी महाशक्तियों ने जमकर लताड़ा जिसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान चिकनी-चुपड़ी बातें करने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध न करने की पाकिस्तानी नीति भी इस बात का संकेत है कि भारत के हमलावर रुख से वह भारी दबाव में है। मसूद की बीमारी का प्रचार कर वह उस दबाव को कम करने की कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन उसकी विश्वसनीयता चूंकि न के बराबर है इसलिए उस पर किसी को भरोसा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि पुलवामा हमले के बाद सेना को पूरी छूट देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और उसी के परिणामस्वरूप वायुसेना ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर बम गिराए। इस हमले के बाद भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता था। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, द. अफ्रीका जैसे देशों ने भारतीय कार्रवाई का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिए भी कहा। इसी का प्रभाव हुआ जो हमेशा ऐंठ कर बात करने वाले पाकिस्तान के मुंह से मिल-बैठकर बातचीत के जरिये विवाद सुलझाने जैसी बातें निकलने लगीं। चूंकि चीन ने भी पाकिस्तान को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया उसके कारण वहां की सरकार और सेना दोनों का मनोबल गिर गया। ये भी संभव है कि इमरान खान को भारत की तरफ से इस तरह के आक्रामक रवैये की उम्मीद नहीं रही होगी। पठानकोट और उरी पर हुए हमले के बाद भी मोदी सरकार ने हालांकि बदला लेने की बात कही तथा थलसेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की किन्तु वह पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान के जवाबी हमले में एक एफ-16 लड़ाकू विमान को गिराकर भारतीय वायुसेना ने अमेरिका तक को चौंका दिया। ये सब देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान में घुसकर मारने और वायु सेनाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई जारी रखने जैसी बातें आश्वस्त करने वाली हैं। ये मुहिम कब तक चलेगी कहना कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और अपनी घरेलू स्थितियों की वजह से इमरान सरकार ज्यादा प्रतिरोध करने में भी सक्षम नहीं है। यूं भी यदि पाकिस्तान आतंकवाद से मुक्त हो सका तो ये उसके लिए भी लिए भी बेहतर होगा। भारत को चाहिए वह इन अनुकूल हालातों का पूरा-पूरा फायदा उठाए और इस अभियान को पूर्णता तक पहुंचाए। रही बात चुनाव और आचार संहिता की तो बाकी सब बातें देश की सुरक्षा के आगे महत्वहीन हैं। इनसान जैसे माहौल या संगति में रहता है, उसका मन और विचार वैसे ही हो जाते हैं। इमरान खान भी उन संकीर्ण सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं, जो हमेशा भारत के प्रति बुरी नीयत रखते हैं। पाकिस्तान में न तो मजबूत लोकतंत्र है और न ही वहां के सत्ताधारी कोई भी फैसला लेने में आजाद हैं। परवेज मुर्शरफ का अपने देश से भागना और बेनजीर भुट्टो को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा का फरमान जारी करना पाक की हकीकत को बयां करता है। कश्मीर पर भी इमरान खान का रवैया उचित नहीं है। अब भारत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान पर आंखें मूंदकर विश्वास करने की गलती नहीं करनी चाहिए।

आपकी बात

महिलाएं सबला बनें

संविधान में भी सैद्धांतिक रूप से बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार की व्यवस्था के बावजूद देश में महिलाएं उत्पीड़ित हैं, अबला ही बनी हुई हैं। अनपढ़, रूढ़िवादी, समाज में यह स्थिति और भी विषम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि यहां आज भी पुरुष प्रधान समाज है। अकेली महिला चाहे वह विधवा हो या परित्यक्ता उसे हीन या बेचारी समझा जाता है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम में साक्षरता एवं अन्य आर्थिक प्रवृत्ति शामिल कर सरकार नारी उत्थान में सक्रिय है। पर इन कार्यों में सरकार की पूर्ण सफलता स्वयं महिलाओं के सहयोग पर ही निर्भर है। महिलाओं में जन-जाग्रति और आत्मविश्वास जाग्रत हो तथा आत्महीनता व विस्मृति के बजाए आत्मचेतना जाग्रत हो। यह स्पष्ट है कि एक साथ शैक्षिक और सामाजिक रूपांतरण की कोशिश में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक इन उद्देश्यों के समर्थन में जनआंदोलन नहीं होगा और नारी जाति स्वयं इससे नहीं जुड़ेगी।

सार्थक लोहमी
रामपुर रोड, हल्द्वानी

कार्बन गैसों से खतरा

अमेरिका में कार्बनडाई ऑक्साइड गैस के कारण एक स्थान पर बड़ा सा स्टोन बन गया है। वैज्ञानिकों ने इसके बनने का कारण कार्बन गैसों को बताया है। यह स्टोन वातावरण व जीवों के लिए खतरनाक है। इस स्टोन को नष्ट करने में करोड़ों रुपया लग सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और विकसित देश दुनिया में सबसे अधिक कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के 20 प्रतिशत लोग दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग करते हैं। वातावरण में बढ़ती कार्बनडाई ऑक्साइड का यह मुख्य कारण है। कार्बन गैस की अधिकता के कारण कहीं दूसरी जगह भी ऐसे स्टोन बन सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वातावरण को प्रदूषित न करें और आने वाले प्राकृतिक खतरे को रोकें। वरना यह स्टोन भारत में भी बन सकते हैं। इसलिए सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय लोगों को प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाये। वन क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन गैसों की मात्रा प्राकृतिक रूप से कम हो जायेगी।

दिव्यांश राजपूत
पीपीजे सरस्वती विहार, नैनीताल

ईर्ष्या की गिरफ्त में जकड़े हम लोग

इस सृष्टि की उत्पति के साथ ही हर जीव में जहां गुणों का विकास हुआ, वहीं कुछ अवगुण भी विकसित हुए और उनमें ईर्ष्या एक प्रमुख अवगुण है। प्राणीमात्र में नैसर्गिक रूप से जमने वाले इस अवगुण को मानव ने अपनी प्रगति के साथ अधिक अंगीकार किया, ज्यों ज्यों उसमें चेतना का विकास होता गया, त्यों-त्यों यह अवगुण भी विभिन्न रूपों में विकसित होने लगा। आज इस अवगुण ने पूरे मानव समाज को अपनी गिरफ्त में कैद कर रखा है और विशेषकर महिलाओं में यह रोग अधिक व्याप्त है। वैसे प्रशंसा व ईर्ष्या का संबंध उसी तरह का है, जैसे नदी व नाव का। ईर्ष्या का चोली-दामन का संबंध प्रशंसा से है। जहां हमने किसी की प्रशंसा की, बस वहां ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। ईर्ष्या ने हर क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो अथवा राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक। यहां तक कि हर घर में भी यह अपने आपको अति शोभनीय व सम्मानीय मानती है। अगर बहू ने अच्छा खाना बनाया है और ससुर ने या पति ने उसकी तारीफ कर दी तो सास व ननद के मन में स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है और बहू की खुशी एक कोने में जा बैठती है। इन दिनों मानव मात्र की एक सामान्य प्रकृति बन गई है कोई किसी को सुखी या खुश नहीं देख पाता, अगर कोई महिला किसी भी परिचित से शिष्टाचारवश हंसकर दो बातें कर लेती है तो उसका अंदाज भी गलत ही लगाया जाता है। नौकरीपेशा महिलाओं को कई बार घरेलू महिलाओं के तानों- उलाहनों एवं व्यंग्यों का शिकार होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें तो एक-दूसरे की उन्नति देखकर खुश होना चाहिए। प्रत्येक पुरुष, महिला एवं बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए, लेकिन हम किसे दोष दें, यह परम्परा तो सदियों से चली आ रही है। यहां तक कि मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी इसके शिकार हुए हैं। इतिहास गवाह है कि इसी ईर्ष्या ने कौरव पांडव में महाभारत का युद्ध करवाया, मां कैकेपी ने राम भगवान को चौदह वर्ष का वनवास दिलवाया और राजा-महाराजाओं में आपसी फूट करवाई। इस रोग से कुछ अंश तक पूरा मानव समाज ग्रस्त है। उसका विस्तार अब कार्यालयों में भी हो गया है। अगर कोई अधिकारी या बाबू ईमानदारी से कार्य करते हैं व उनकी प्रशंसा होती है तो उनके साथी उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह भावना बच्चों में भी देखी गई है। बड़ा भाई पढ़ाई में तेज है और हमेशा अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होकर प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है तो छोटे भाई के दिल में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है और वह हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि उसका भाई परीक्षा में असफल हो। अगर हमारे देश में यही सब होता रहा तो हम सब एक होकर भी अलग हैं। अगर हम सब मिलकर यह सोच लें कि दूसरों की सफलता में ही हमारी सफलता है तो अवश्य ही एक दिन हमारा देश, समाज व परिवार खुशहाल व समृद्ध होगा। आखिर ईर्ष्या ही तो ईर्ष्या को बढ़ावा देती है और वह कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जाती है। ईर्ष्या के भी विभिन्न रूप हैं यह भी कई रूपों में प्रकट होती है मिसेज शर्मा को ही देखो अपनी सहेली से वह बड़ी खुशमिजाजी से मिलती हैं और उसके मुंह सामने उसकी प्रशंसा के पुल बांध देती हैं, लेकिन उनकी सहेली के मुंह फेरते ही वह औरों के घर जाकर उसके बारे में तरह-तरह की झूठी-सच्ची बातें करती हैं। यह भी ईर्ष्या का रूप है। ऐसे मुख में राम बगल में छूरी रखने वाले लोग आखिर कौन से समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे एक परिचित हैं उनके दो लड़के हैं। बड़े लड़के का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से हुआ है और छोटे लड़के की पत्नी एक अमीर घराने की लड़की है, वह गृहस्थी के कार्यों से अनभिज्ञ है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से वह कटु व्यवहार करती है और बात-बात पर अपने पिता के घर से मिले दहेज के बारे में बखान करती है, लेकिन फिर भी उसे बड़े लाड़-प्यार से रखा जाता है और सास-ससुर उससे हाथों में उठाए रखते हैं, प्रत्येक सदस्य उसका सम्मान करता है और उसकी तारीफ की जाती है, जबकि दूसरी ओर उसकी बहू जो कि घरेलू कार्यों में निपुण, सुंदर, सुशील होने के साथ-साथ मृदु भाषिणी है और अपने सरल व मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन बदले में उसे तिरस्कार व अपमान ही मिलता है। आए दिन उसकी प्रताड़ना के नए कारण ढूंढ लिए जाते हैं और एक दिन वही होता है जो आज इस सदी की सामाजिक सभ्यता बन गई है, उसे या तो फिर घासलेट ढूंढना पड़ता है या नींद की गोलियां। उसकी योग्यता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। यह भी ईर्ष्या का एक वीभत्स रूप है। ऐसे ईर्ष्यावान लोग न सिर्फ अपने परिवार की शांति समाप्त कर लेते हैं, बल्कि समाज के लिए कलंक बनकर रह जाते हैं। हमारे राष्ट्र का हित होने के बजाय अहित ही होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अयोग्य को योग्य बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन योग्य से ऐसी बातें न कहें कि उसके दिल पर आघात पहुंचे। व्यक्ति में अगर एक बुराई है तो उस बुराई को समाप्त करें। ऐसा नहीं कि उस बुराई के साथ-साथ उसकी अच्छाइयां (गुण) भी खत्म हो जाएं और वह किसी भी लायक नहीं रहे।

विद्या जोशी